

कांट्रैक्ट फार्मिंग से खिले हरालदासपुर के किसानों के चेहरे

हुगली/कोलकाता : हुगली के हरालदासपुर के किसानों के लिए मंगलवार दोहरी खुशी का दिन था. आलू की अच्छी कीमत मिलने से गदगद किसानों का हौसला पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें सम्मानित कर बढ़ाया. दरअसल, पेप्सिको की पहल से ही यहां के किसानों ने कांट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की और अब उन्हें उपज की अच्छी कीमत मिलने की चिंता नहीं रही. खास बात

यह कि उन्हें अब सामान्य आलू के मुकाबले प्रति बीघा 10 से 12 हजार की अधिक राशि का फायदा होता है. न खेती के लिए पूंजी की चिंता और न ही फसल खराब होने की परवाह. भारतीय स्टेट बैंक से सहज कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है, वहीं फसल का बीमा भी हो जाता है. फसल बोनस से लेकर तैयार होने तक पेप्सिको के प्रतिनिधि किसानों के साथ हमकदम होते हैं और विशेषज्ञों की तरह मागदर्शन करते हैं. एक तकरीबन 4 एकड़ भूमि पर आलू की खेती कर

रहे मधुसूदन मंडल कहते हैं: जब कंपनी के प्रतिनिधि ने उनसे नयी किस्म के आलू की खेती के लिए संपर्क साधा, तो संशय था. पर आज उनकी देखादेखी कुल 110 एकड़ भूमि में आलू की खेती होने लगी. एक अन्य किसान संजय कुमार नंदी भी मंडल का समर्थन करते हुए जोड़ते हैं: प्रति एकड़ 12 टन आलू का उत्पादन होता है, जो सामान्य आलू से डेढ़ गुना ज्यादा है. इसी वजह से हम कुल तीन एकड़ में द्वाइ एकड़ भूमि पर आलू की खेती करते हैं. वह आगे कहते हैं कि अब बैंक के

चलते महाजनों पर निर्भरता नहीं रही. एक और किसान राम प्रकाश घोषाल ने बताया कि कांट्रैक्ट फार्मिंग की बड़ी खूबी है कि फसल लगाते ही मिलने वाली कीमत का पता चल जाता है. इससे किसान दोगुने उत्साह से मेहनत करते हैं. उन्होंने बताया कि अभी सामान्य आलू की कीमत एक से डेढ़ रुपये प्रति किलो है, वहीं उनका आलू 5 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की दर से बिका है. पेप्सिको के कार्यकारी उपाध्यक्ष (एगो) निखित भाटिया ने बताया कि बंगाल के छह जिलों में वर्ष

2004 में 400 एकड़ जमीन पर आठ सौ किसानों ने कांट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी. आज इससे जुड़े किसानों की तादाद बढ़ कर छह हजार हो गयी है. वहीं, द्वाइ हजार एकड़ भूमि में खेती हो रही है. पेप्सिको एगो के महाप्रबंधक प्रताप बोस ने बताया कि अगले वर्ष किसानों की तादाद बढ़कर 11 हजार हो जाने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि बंगाल की इकाई को 30 हजार टन प्रतिवर्ष आलू की जरूरत होती है. निकट भविष्य में खपत 70-80 टन हो जाने की उम्मीद है.